

## CORPORATE OFFICE

### Delhi Office

706 Ground Floor Dr. Mukherjee  
Nagar Near Batra Cinema Delhi -  
110009

### Noida Office

Basement C-32 Noida Sector-2  
Uttar Pradesh 201301



दिनांक: 30 सितम्बर 2023

## गोबरधन योजना

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "गोबरधन योजना" शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के "अर्थव्यवस्था" खंड में प्रासंगिक है।

### प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- गोबरधन योजना क्या है?

### मुख्य परीक्षा के लिए:

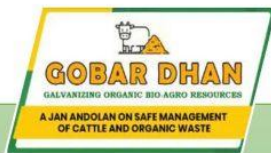
- सामान्य अध्ययन-2: अर्थव्यवस्था

### सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने देश भर में सीबीजी और बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए गोबरधन के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल शुरू किया।

### गोबरधन योजना-

- गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज़-धन) योजना भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को धन में बदलने और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है।
- इसका उद्देश्य बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी)/जैव-संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संयंत्रों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भारत के जलवायु कार्रवाई उद्देश्यों को संबोधित करना है।
- गोबरधन योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-चरण 2 की एक उप-योजना है।
- जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) गोबरधन के लिए नोडल विभाग है।



## Objectives

- Efficient Organic Waste Management
- Soil Organic Carbon Enhancement
- Promotion of Organic Farming Practices

## गोबरधन योजना को सक्षम करने वाली पहल:-

### बाजार विकास सहायता (MDA):

- **उर्वरक विभाग** ने गोबरधन बायोगैस संयंत्रों से प्राप्त जैविक उर्वरकों के उत्पादन और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) कार्यक्रम लागू किया है।
- एमडीए के लिए तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) में 1451.82 करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है।
- एमडीए का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना और कृषि प्रथाओं में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
- कार्यक्रम दो प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है: दो उद्देश्य हैं: गाँवों को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना।

## गोबरधन को सक्षम करने वाली अन्य पहल:-

### जैव-घोल का मानकीकरण:

- बायोगैस के उत्पादन से बायो-स्लरी नामक एक उपोत्पाद बनता है, जिसमें जैविक खेती के तरीकों के उपयोग को बढ़ाने और किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने की महत्वपूर्ण क्षमता है।
- जैविक उर्वरक के रूप में जैव-स्लरी की दक्षता में सुधार के लिए इसके उत्पादन और अनुप्रयोग को मानकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

### एआईएफ और एएचआईडीएफ में सीबीजी संयंत्रों का समावेश:

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों को कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) और पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) में शामिल किया है।
- सीबीजी संयंत्रों के विकास और वित्तीय सहायता को आरबीआई की मान्यता और समर्थन द्वारा सुगम बनाया गया है, जिससे गोबरधन योजना की सफलता को और बल मिलता है।

### सीबीजी संयंत्र श्रेणियों के वर्गीकरण:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सीबीजी संयंत्र श्रेणियों के वर्गीकरण और अंशांकन को संशोधित किया है।
- यह कदम सुनिश्चित करता है कि सीबीजी संयंत्रों का मूल्यांकन और विनियमन प्रभावी ढंग से किया जाता है, जिससे उनकी दक्षता और समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है।

### अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम का पुनरुत्थान:

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपशिष्ट से ऊर्जा योजना को पुनर्जीवित किया है, जो गोबरधन योजना का पूरक है।
- इस पहल से सर्कुलर इकोनॉमी रणनीति को और भी समर्थन मिलता है, जो जैविक कचरे सहित विभिन्न कचरे को ऊर्जा में बदलने को प्रोत्साहित करता है।

## लाभ और प्रभाव:-

- **स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन:** सीबीजी/बायोगैस की ओर बदलाव भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में योगदान देता है, ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य सुनिश्चित करता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।
- **ग्रामीण रोजगार के अवसर:** बायोगैस संयंत्रों की स्थापना अर्ध-कुशल और कुशल श्रम के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **महिला सशक्तिकरण और बेहतर स्वास्थ्य:** सीबीजी/बायोगैस के माध्यम से स्वच्छ ईंधन तक पहुंच से गाँवों में स्वच्छता में सुधार होता है, बीमारियों का प्रसार कम होता है और ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं को लाभ होता है।
- **सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी):** गोबरधन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है जैसे- **सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी):** गोबरधन **एसडीजी-3** (स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा), **एसडीजी-6** (स्वच्छ जल और स्वच्छता), **एसडीजी-7** (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा), **एसडीजी-13** (जलवायु कार्रवाई) आदि।

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था:** गोबरधन कूड़े को उपयोगी संसाधनों में बदलकर और दीर्घकालिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली की वकालत करके चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय ([pib.gov.in](http://pib.gov.in))

### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

**प्रश्न-01.** गोबरधन योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) गोबरधन के लिए नोडल विभाग है।
2. कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों को कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) और पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) में शामिल किया गया है।
3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपशिष्ट से ऊर्जा योजना को पुनर्जीवित किया है, जो गोबरधन योजना का पूरक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

**प्रश्न-02.** निम्नलिखित पर विचार करें:

1. गांवों में प्रमुख ठोस कचरे के प्रबंधन में मदद करना।
2. चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
3. गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता और स्वास्थ्य।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना

उपर्युक्त में से कितने गोबरधन के लाभ हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) उपर्युक्त में सभी।

उत्तर: (C)

### मुख्य परीक्षा प्रश्न-

**प्रश्न-03.** चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और भारत के जलवायु कार्रवाई उद्देश्यों को प्राप्त करने में गोबरधन योजना की प्रमुख पहलों और प्रभावों पर चर्चा करें?

Rajiv Pandey

## मनकोम्बु संबासिवन स्वामिनाथन

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "एमएस स्वामीनाथन" शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के कृषि खंड में प्रासंगिक है।

### प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- एमएस स्वामीनाथन के बारे में?

## मुख्य परीक्षा के लिए:

- सामान्य अध्ययन-03: कृषि
- एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशें?
- हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में स्वामीनाथन की भूमिका?
- सदाबहार क्रांति की जरूरत है?

## सुर्खियों में क्यों:

- प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और देश की 'हरित क्रांति' में अहम योगदान देने वाले डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन जिनका हाल ही में निधन हो गया।

## प्रारंभिक जीवन और शिक्षा-

- तमिलनाडु के कुंभकोणम में 7 अगस्त, 1925 को जन्मे, शुरू में सिविल सेवा में अपना करियर बनाने की इच्छा जताई और सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया।
- कृषि के प्रति उनके जुनून के कारण भारत छोड़ो आंदोलन और 1942-1943 के बंगाल के अकाल जैसे विचारों ने उनका ध्यान वापस इस ओर केंद्रित कर दिया।
- कृषि में अपनी गहन रुचि को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोयंबटूर कृषि कॉलेज में दाखिला लिया।

## कृषि के क्षेत्र में विविध भूमिकाएं-

- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।
- उनके उल्लेखनीय पदों में 1981 से 1985 तक खाद्य और कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष, 1984 से 1990 तक प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष और 1989 से 1996 तक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (भारत) के अध्यक्ष शामिल थे।
- इसके अलावा, उन्होंने अन्य कर्तव्यों के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक जैसे उल्लेखनीय पदों पर कार्य किया।
- उन्होंने 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए किसानों को सहायता प्रदान की।

## एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशें:-

एमएस स्वामीनाथन आयोग, जिसे किसानों पर राष्ट्रीय आयोग भी कहा जाता है, ने कई सिफारिशें कीं, जिनमें भारतीय किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने और टिकाऊ कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की कार्रवाइयां शामिल हैं। **मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:**

- **सार्वजनिक निवेश में वृद्धि:** सार्वजनिक निवेश में वृद्धि: कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए, जिसमें सिंचाई, जल निकासी, भूमि का विकास, जल संरक्षण, अनुसंधान और विकास और संपर्क सड़कें शामिल हैं।
- **एमएसपी का प्रवर्तन:** आयोग वैश्वीकरण के सामने किसानों के हितों की रक्षा करने और उनके लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को समान रूप से लागू करने के महत्व पर जोर दिया।
- **C2 + 50%:** आयोग एमएसपी को ऐसे स्तर पर स्थापित करने की सलाह देता है जो व्यापक लागत (सी2) पर 50% मार्जिन प्रदान करता है, जिसमें पारिवारिक श्रम की अनुमानित लागत, स्वामित्व वाली भूमि का किराया और स्वामित्व वाली पूंजी पर लगाया गया ब्याज शामिल है।
- **एक राष्ट्र-एक बाजार:** आयोग व्यापारी गुटबंदी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की सिफारिश करता है, जिसे "एक राष्ट्र-एक बाजार" के रूप में भी जाना जाता है।
- **बाजार विकास:** यह स्थानीय उपज के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के विकास और सड़क कर और स्थानीय करों को समाप्त करके माल की आवाजाही के सरलीकरण की वकालत करता है।



- **भूमि सुधार:** आयोग के अनुसार, अधिशेष और बंजर भूमि को वितरित किया जाना चाहिए, प्रमुख कृषि भूमि और जंगलों को गैर-कृषि उपयोगों के लिए नहीं बदला जाना चाहिए, और आदिवासी समूहों और चरवाहों को चराई के अधिकार और मौसमी वन तक पहुंच मिलनी चाहिए।
- **राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाहकार सेवा:** एक ऐसी सेवा स्थापित करें जो स्थान और मौसम-विशिष्ट आधार पर पारिस्थितिक, मौसम विज्ञान और विपणन कारकों के साथ भूमि उपयोग निर्णयों को जोड़ सके।
- **भूमि बिक्री का विनियमन:** पारसल के आकार, इच्छित उपयोग और खरीदार के प्रकार जैसे तत्वों के आधार पर कृषि भूमि की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें।
- **जल प्रबंधन:** जल प्रबंधन में पानी तक न्यायसंगत और दीर्घकालिक पहुंच को प्रोत्साहित करना, जलभृत पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल आपूर्ति बढ़ाना और सिंचाई उद्योग में महत्वपूर्ण निवेश करना शामिल है।
- **ऋण पहुंच:** गरीबों की औपचारिक ऋण प्रणालियों तक पहुंच बढ़ाने की क्षमता बढ़ाना, फसल ऋण पर ब्याज दर कम करना और जब लोग वित्तीय संकट में हों तो ऋण स्थगन लागू करना।
- **कृषि जोखिम निधि:** प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों को राहत प्रदान करने के लिए एक कृषि जोखिम कोष की स्थापना।
- **महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड:** महिला किसानों को संयुक्त स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।
- **फसल बीमा:** कम प्रीमियम और ग्रामीण बीमा विकास कोष की स्थापना के साथ, सभी फसलों और पूरे देश में फसल बीमा कवरेज बढ़ाएँ।
- **आजीविका संवर्धन:** बेहतर वित्तीय सेवाएँ, बुनियादी ढाँचा, मानव विकास और व्यवसाय विकास सेवाएँ वंचितों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।
- **हेल्थकेयर:** आत्महत्या हॉटस्पॉट स्थानों पर ध्यान देने के साथ सस्ती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पुनर्जीवित करें।
- **किसान आयोग:** किसानों के मुद्दों पर गतिशील सरकारी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय किसान आयोगों की स्थापना।
- **आजीविका के लिए माइक्रोफाइनेंस:** आजीविका वित्त के रूप में सेवा करने के लिए माइक्रोफाइनेंस नीतियों का पुनर्गठन करना, समर्थन सेवाओं के साथ ऋण प्रदान करना।
- **कम लागत वाली प्रौद्योगिकियाँ:** किसानों की आय को अधिकतम करने के लिए कम जोखिम और कम लागत वाली कृषि प्रौद्योगिकियों की सिफारिश करें।
- **बाजार हस्तक्षेप योजनाएं:** जीवन रक्षक फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजनाओं को लागू करना और मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना करना।
- **ग्राम ज्ञान केंद्र: कृषि और गैर-कृषि आजीविका पर जानकारी प्रदान करने के लिए ग्राम ज्ञान केंद्र स्थापित करना।**
- **आय समानता:** यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य है कि किसानों की शुद्ध टेक-होम आय सिविल सेवकों के बराबर हो।
- **नस्ल संरक्षण:** उपयोग के माध्यम से समुदाय-आधारित नस्ल संरक्षण को प्रोत्साहित करें।

### **हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में स्वामीनाथन की भूमिका:**

- **फसल सुधार:** स्वामीनाथन ने चावल और गेहूं पर विशेष जोर देने के साथ फसल की किस्मों के सुधार के लिए अपने प्रयासों को फसल सुधार पर केंद्रित किया।
- **अर्ध-बौना गेहूं की किस्मों के अग्रणी:** उन्होंने अर्ध-बौने गेहूं की किस्मों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, जो ठहरने (तने का झुकना) को कम करने और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बनाई गई थीं।
- **नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग:** गेहूं के उपभेदों में बौने जीन को पेश करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर काम किया। जिसे "गेहूं क्रांति" के रूप में जाना जाने लगा।
- **हरित क्रांति की चुनौतियों की स्वीकृति:** स्वामीनाथन हरित क्रांति के कारण आने वाली कठिनाइयों से अच्छी तरह परिचित थे, जैसे पारंपरिक फसल किस्मों का उन्मूलन, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की चिंता और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग।

- इसके अतिरिक्त, उन्होंने भूजल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले खतरों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए टिकाऊ कृषि पद्धतियों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

### सदाबहार क्रांति की आवश्यकता:-

- डॉ. एम ने सबसे पहले "हरित क्रांति" की धारणा प्रस्तावित की। एस. स्वामीनाथन ने पर्यावरण या समाज को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि उत्पादकता को लगातार और निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- स्वामीनाथन ने "हरित क्रांति" जहां उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि खाद्य उत्पादन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है। मुख्य लक्ष्य कम पानी, कम कीटनाशक और कम भूमि सहित कम संसाधनों का उपयोग करते हुए पैदावार बढ़ाना है। कृषि की दीर्घायु और पर्यावरणीय अनुकूलता सुनिश्चित करके, इस क्रांति का लक्ष्य इसे टिकाऊ और निरंतर तरीके से बेहतर बनाना है।

### अनुशंसित किए गए उपाय:

- **पोषक तत्वों से भरपूर दालें:** कुपोषण से निपटने के लिए उच्च पोषक तत्वों के साथ दालों के उत्पादन को बढ़ाना।
- **क्षेत्रीय फसल विविधीकरण:** कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए, क्षेत्रीय फसल विविधीकरण मिट्टी के प्रकार और जलवायु के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलों की पहचान करना।
- **पारिस्थितिक एकीकरण:** कृषि क्रांति की प्रभावशीलता में सुधार के लिए वैज्ञानिक तरीकों के साथ पारिस्थितिक विचारों को शामिल करना।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन का मूल्यांकन करने के लिए किसानों को पूर्वानुमानित अनुसंधान में शामिल करना।
- **संसाधन दक्षता:** दीर्घकालिक स्थिरता के लिए, भूमि, कीटनाशकों, उर्वरकों और पानी जैसे कम संसाधनों के साथ अधिक पैदावार के लिए प्रयास किया जाना।
- **अभिनव प्रौद्योगिकी:** किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बुवाई मार्गदर्शन और बाजार मूल्य प्रदान करने के लिए अभिनव सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईटीसी) उपलब्ध कराना।
- **ई-क्रांति सेवा:** किसानों को कीमतों, ऑनलाइन बैंकिंग और अपनी उपज को ऑनलाइन खरीदने या बेचने के विकल्प के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ई-क्रांति सेवा को लागू करें।
- **जीएम खाद्य फसलें:** पैदावार को बढ़ावा देने, बीमारियों और कीटों का विरोध करने और पर्यावरणीय तनावों का प्रबंधन करते हुए पोषण बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य फसलों को पेश करें।
- पैदावार बढ़ाने, कीटों और बीमारियों से बचाव और पर्यावरणीय तनाव को कम करते हुए पोषण में सुधार करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

### पुरस्कार और सम्मान-

- स्वामीनाथन को भारत के गेहूं और चावल उत्पादन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार के उद्घाटन प्राप्तकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया था।
- उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और योगदान के लिए उन्हें भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

स्रोत:<https://indianexpress.com/article/explained/ms-swaminathan-father-green-revolution-explained-8959892/>

### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

#### प्रश्न-01 भारतीय कृषि में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हरित क्रांति मुख्य रूप से अनाज के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित थी, जबकि सदाबहार क्रांति में फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
2. फसलों का विविधीकरण और फसल रोटेशन सदाबहार क्रांति के प्रमुख घटक हैं।
3. नॉर्मन बोरलॉग को अक्सर "सदाबहार क्रांति के पिता" के रूप में जाना जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. उपर्युक्त सभी।
4. उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर: B

प्रश्न-02 भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) भारत में उगाई जाने वाली सभी फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है।
2. एमएसपी का निर्धारण प्रत्येक फसल के लिए उत्पादन लागत 'ए2+एफएल' के आधार पर किया जाता है।
3. केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) एमएसपी स्तरों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4. एमएसपी का मुख्य उद्देश्य खाद्य कीमतों को स्थिर रखकर और मुद्रास्फीति को रोककर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. उपर्युक्त सभी।

उत्तर: b

**मुख्य परीक्षा प्रश्न-**

प्रश्न-03 भारतीय कृषि और समाज पर हरित क्रांति के बहुआयामी प्रभाव का आकलन कीजिए। भारत में सतत और न्यायसंगत कृषि विकास प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Rajiv Pandey

